

SHRI MANUBHAI PATEL: It is a breach of privilege. How do you compare like that? Being a senior parliamentarian, can't you distinguish between the two?

SHRI BHUPESH GUPTA: Now Mr. Patel and others are sitting. Here is another Chief Minister. Well, my friend is sitting there. They are all honourable men. I do not dispute that. But how do they feel? Tell me privately at least on telephone how do you feel? Do you feel very comfortable? Well, it does not behove anybody to assail Mr. Sanjay Gandhi—of course Sanjay Gandhi must be assailed; I am one of those who are for it—but defend Mr. Kanti Bhai Desai. I find Mr. Kanti Bhai Desai is being defended in the same way by the treasury benches as in the emergency days the other son of the Prime Minister was defended. We do not like this.

So, Sir, all I say is that we are all unanimous in this matter despite our differences. We do not say we agree on every thing. But this demand we make in the interest of public morality, democracy and parliamentary institutions and I hope, Sir, next week, as my friend has suggested, this debate must get the priority.

SHRI SANKAR GHOSE: Sir, we want a statement from the Minister of Parliamentary Affairs.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us go to the Calling Attention Motion. Mr. Kalp Nath Rai. (Interruption).

SHRI MANUBHAI PATEL: Statement was already made. He was absent.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Calling Attention. Mr. Kalp Nath Rai.

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर है। उपसभापति महोदय, आप ही इस का निर्णय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप यहां इस का निर्णय नहीं करते तो इसको आप अध्यक्ष महोदय के पास ले जायें। बहुत से महत्वपूर्ण

विषय हैं कि जो हम लोग कालिंग अटेंशन के जरिये उठाने के लिये आप के पास भेजते हैं, लेकिन वे विषय यहां पर कालिंग अटेंशन के लिये मंजूर नहीं किये जाते और लोक सभा में वे विषय ले लिये जाते हैं और उनके लिये वहां उन को मंजूरी मिल जाती है। जैसे यू एन स्टेडी :

श्री उपसभापति माननीय सदस्य पहले भी यह बात कह चुके हैं। आप घंटा भर बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए, लेकिन इस के लिये व्यवस्था का प्रश्न उठा कर न बोले। इस में व्यवस्था के प्रश्न की कोई बात नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कालिंग अटेंशन में महत्वपूर्ण विषय को आप मंजूर नहीं करते हैं लेकिन देश के लिये वे विषय महत्वपूर्ण होते हैं और आज स्थिति यह है कि वे विषय लोक सभा में मंजूर कर लिये जाते हैं और उन पर मंत्रीगण अपने बयान देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उन की प्रतिक्रिया होती है। हम लोगों को उन विषयों को उठाने से वंचित किया जाता है और उन मौकों से वे लोग लाभ उठाते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्वाइंट है जो आप के पास है काश्मीर में जो यू एन स्टेडी हुई उस के लिये हम लोगों ने आप के पास कालिंग अटेंशन के लिये भेजा है। आप उस को मंजूर कीजिए। इसी तरह से और भी विषय हैं जिन को मंजूर किया जाना चाहिए।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The situation arising out of the acute shortage and non-availability of Kerosene and Diesel in various parts of the country

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में मिट्टी के तेल तथा डीजल की भारी कमी तथा उन के उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति और इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा

[श्री कल्प नाथ राय]

उठाये गये कदमों की ओर पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री
(श्री हेमवती नन्दन बहगुणा) : श्रीमन, माननीय सदस्यों ने देश के विभिन्न भागों में मिट्टी के तेल और डीजल की बेहद कमी तथा इनके उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न परिस्थिति तथा इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

मैंने इस सदन में दिनांक 24 नवंबर, 1978 को दिए गये वक्तव्य में पहले ही इस बात का उल्लेख कर दिया था कि देश भर में कुल मिलाकर सप्लाई संबंधी स्थिति जबकि संतोषजनक है वहां पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र के भाग में, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली आते हैं, डीजल तेल की उपलब्धता संबंधी कुछ समस्याएँ रही हैं। जिन अनेक प्रतिकूल बातों में कठिन उत्पाद संबंधी सप्लाई, परिस्थिति उत्पन्न हुई उनका उल्लेख मैंने सदन में दिनांक 24 नवम्बर, 1978 को प्रस्तुत अपने वक्तव्य में किया था।

तब से इस स्थिति में कुछ सुधार हुए हैं। पत्तन तथा गोदी कामगरोँ की हड़ताल, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती थी, समाप्त कर दी गयी है। इसके अलावा बरौनी तेल शोधक कारखाने के विभिन्न संघों के साथ किए गये विचार विमर्श के बाद इस शोधन शाला में इस माह के प्रारम्भ से अब तक दैनिक कच्चे तेल के उत्पादन को कुल मिलाकर सामान्य स्तर तक पुनः ला दिया गया है। बरौनी में अब जो अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध है उन्हें पाइपलाइन के जरिये कानपुर भेजा जा रहा है जो कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मांग पूरा करने वाला स्थान है। इससे पहले बरौनी शोधनशाला में श्रमिक संबंधी समस्याओं

के कारण उत्पादन में हाताही जाने के परिणामस्वरूप कानपुर में उत्पाद के बहुत कम भण्डार को ध्यान में रखते हुए, कानपुर से विभिन्न डिपो तक, इन उत्पादों को रेल द्वारा ले जाने से संबंधित स्थिति पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा था। कानपुर में इन उत्पादों की उपलब्धता में पहले से ही सुधार होने लग गया है और कानपुर में इन उत्पादों की उपलब्धता तथा रेल से मान ले जाने संबंधी स्थिति में शीघ्र सुधार हो जाने की आशा है। इससे इन उत्पादों को उत्तर पश्चिम प्रदेश के विभिन्न डिपुओं तक और तेजी से ले जाना सुनिश्चित हो जायेगा।

तब से उत्तर पश्चिम प्रदेश के भागों में डीजल की सप्लाई संबंधी स्थिति में पहले से सुधार हो गया है, यद्यपि इस स्थिति में अभी पूरी स्थिरता आनी बाकी है। उत्तर पश्चिम प्रदेश में नवम्बर माह के दौरान डीजल तेल की जो वास्तविक बिक्री हुई है वह पिछले वर्ष नवम्बर, के दौरान इस उत्पाद की बिक्री की अपेक्षा कहीं अधिक है। इसी प्रकार से दिसम्बर, के पहले 6 दिनों के दौरान इस सारे प्रदेश में डीजल की जो बिक्री हुई है वह भी दिसम्बर 1977 के दौरान इस उत्पाद की दैनिक औसत बिक्री की तुलना में लगभग 14% अधिक है।

जहां तक मिट्टी के तेल का संबंध है, यहां इस बात का उल्लेख कर दिया जाये कि साफ्ट कोक जैसे अन्य वैकल्पिक ईंधनों के अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण पिछले कुछ महीनों में इस उत्पाद की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देश भर में मिट्टी के तेल की सप्लाई, कुल मिलाकर सामान्य है और उत्तर पश्चिम प्रदेश में नवम्बर, 1977 के दौरान इस सारे प्रदेश में मिट्टी के तेल की बिक्री की तुलना में नवम्बर, 1978 के दौरान मिट्टी के तेल की बिक्री लगभग 16% अधिक हुई है। फिर भी, पिछले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम प्रदेश के कुछ भागों में मिट्टी के

तेल की उपलब्धता संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसका कारण यह है कि मिट्टी के तेल के भण्डार को, जो कि दिनांक 24 नवंबर, 1978 को दिये गये मेरे वक्तव्य में उल्लिखित कारणों से समाप्त हो गया था इस उत्पादन को लाने ले जाने संबंधी बाधाओं को देखते हुए पुनः एकत्र नहीं किया जा सका।

खपत वाले स्थानों पर इस उत्पाद को उपलब्ध करने से संबंधित स्थिति सुधारने के लिए पहले से ही अनेक कदम उठा लिए गये हैं ये कदम निम्नलिखित हैं :—

I. डीजल तथा मिट्टी के तेल की मांग को पूरा करने के लिए इन उत्पादों को तत्परता से ढोने के लिए रेलवे से बहुत नजदीकी सम्पर्क बनाया हुआ है।

II. प्रत्येक राज्य की राजधानी के लिए तेल कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से नामित विशेष अधिकारी राज्यों सरकारों को इस स्थिति पर पूरी तरह से परामर्श दे रहे हैं ताकि इन उत्पादों के उचित वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। दुर्गम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए तेल कंपनियों द्वारा प्रत्येक डिपो के लिए संयुक्त रूप से नामित अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर इसी प्रकार का सम्पर्क बनाया जा रहा है।

III. अवांछनीय तत्वों द्वारा इन उत्पादों का गला जमा करने तथा चोरबाजारी के विरुद्ध अपेक्षित कदम उठाने के लिए राज्यों सरकारों से भी अनुरोध किया गया है।

ईरान से कच्चे तेल की सप्लाई से संबंधित स्थिति बराबर अनिश्चित बनी हुई है। नवम्बर तथा दिसम्बर, 1978 के दौरान 1.1 मि० मी० टन से कुछ ऊपर कच्चे तेल की योजनाबद्ध उठाने की अपेक्षा ईरान से पहले ही लगभग 0.2 मि० मी० टन कच्चा तेल उठा लिया

गया है। इस अवधि के दौरान वैकल्पिक संसाधनों से लगभग 8 मि० मी० टन कच्चे तेल को उठाने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली गई है। ईरान से कच्चे तेल को उपलब्ध करने से संबंधित स्थिति पर बराबर निगरानी रखी जा रही है और ईरान से उपलब्ध होने वाले कच्चे तेल की और कमी को पूरा करने के लिए अपेक्षित कदम उठाये जा रहे हैं। इसके अलावा मांग को पूरा करने के लिए डीजल तेल तथा मिट्टी के तेल सहित अतिरिक्त उत्पादों का आयात करने के लिए भी कदम उठा लिए गये हैं।

डीजल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई से संबंधित स्थिति का विशेषकर उत्तर पश्चिम प्रदेश में इसका बराबर पुनरीक्षण किया जा रहा है। पहले से उठाये गये कदमों के अनुसरण में गतिशील तथा पर्याप्त मात्रा में रेल की गतिविधि के संबंध में रेल तथा इन उत्पादों के उचित वितरण के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किये जाने वाले सहयोग से इस स्थिति में और सुधार होने की आशा है।

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदय मंत्री महोदय एक बहुत ही कुशल प्रशासक हैं और इनके मंत्रालय में रहते हुए भी इस समय, उत्तर प्रदेश की वही स्थिति हो गई है जो आप पर जब मुख्य मंत्री का भार था 1974 में उस समय भी विलकुल मिट्टी का तेल या डीजल नहीं मिलता था। इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत से किसानों ने मेरे पास पत्र लिखे हैं। आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया; पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसकी जानकारी मुझे है डीजल विलकुल नहीं मिल रहा है।

श्री श्यामलाल यादव (उत्तर प्रदेश) : सारे प्रदेश में नहीं मिल रहा है।

श्री कल्पनाथ राय : सारे प्रदेश में नहीं मिल रहा है। जहां से मेरे पास पत्र आये हैं उन्होंने बताया है कि ट्रैक्टर, हैवे चलने बन्द

[श्री कल्प नाथ राय]

हो गये हैं और पूरे हिन्दुस्तान का उत्तरी भाग, नार्थ इंडिया ही अन्न पैदा करने में सबसे आगे हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। लोग यह कहते हैं कि डीजल के लिये अगर हम दुाना दाम दे दें तो हमें मार्किट में मिल जाएगा लेकिन फेयर प्राइस शाप पर डीजल नहीं मिलेगा। यह संकट उत्तर प्रदेश में है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज की परिस्थिति में जब कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं, दुनिया में डिटांट एक दम असफल सा हो गया है और दुनिया के पैमाने पर साउथ ईस्ट एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं इस स्थिति में तेल का बड़ा महत्व है। तेल के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस को प्राप्त करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिये और तेल के क्षेत्र में मैसिव इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए।

दूसरी बात यह कहनी है कि आज की परिस्थिति में अगर तेल के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता को प्राप्त नहीं किया जाएगा तो Our national sovereignty will be in danger if self-reliance in the field of oil is not achieved. क्योंकि आज हमारी राष्ट्रीय प्रभुता का और तेल का बड़ा गहरा रिश्ता है। ऐसी स्थिति में डीजल के प्रश्न पर बहुगुणा जी जैसे एक कुशल मंत्री का अधिकाधिक ध्यान देना चाहिये जो जनता सरकार है वह पब्लिक सेक्टर को डिस्ट्राय करने पर तुली हुई है। मोरारजी भाई को तो ऐसा लगता है कि पूरे देश की पब्लिक सेक्टर, एकोनोमी को नष्ट करने का एक ठेका ल लिया है। ऐसी स्थिति में मैं जनता सरकार का बड़ा क्रीटीसाइजर हूँ लेकिन इसमें जो समाजवादी, सेक्युलरिज्म नेशनलिज्म डेमोक्रेसी की नीतियों के कठोरतम समर्थक हैं और जवाहरलाल जी के कठोरतम समर्थक

के रूप में बहुगुणा जी कैबिनेट में हैं, वह तेल के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। आज की पूरी दुनिया, देश की आजादी और पूरी नेशनल सीवरेनिटी इस तेल से जुड़ी हुई है। हमें पता है कि हमारे देश में 11 मिलियन मीट्रिक टन तेल पैदा हो रहा है और 13 मिलियन मीट्रिक टन तेल हम विदेशों से मंगा रहे हैं। आदरणीय बहुगुणा जी ने कोशिश करके एक मिलियन मीट्रिक टन रूस से प्राप्त किया है लेकिन 13 मिलियन मीट्रिक टन की तेल की कमी है वह हम ईरान और ईराक से प्राप्त कर रहे हैं। इसी के कारण एक बहुत ही विषम स्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है लेकिन अगर तेल के क्षेत्र में मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जो तेजी से बदल रही हैं डिटांट फेल हो गया है, साउथ ईस्ट एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनोमी डिपेंड करती आ रही है फर्टीलाइजर और तेल के ऊपर, तो यदि तेल के क्षेत्र में मैसिव इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा नहीं होता है तो भारत की आजादी को जवर्दस्त खतरा पैदा हो सकता है। इसी दौर में जो हमारा एनर्जी स्रोत है न्यूक्लियर—इस न्यूक्लियर पालिसी के अगे अमरिकी दबाव में यह जनता सरकार लगातार घुटने टेकती जा रही है। भारत का भविष्य जिस एनर्जी पर मुनसिर करता है, आयल पर मुनसिर करता है और न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारे भविष्य की ओर देश की आजादी की रक्षा करने वाली है इसके लिये जनता सरकार अमरीकी दबाव में आकर घुटने टेकती जा रही है। ऐसी स्थिति में बहुगुणा जी से और कोई निवेदन नहीं कर सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस तेल के क्षेत्र में मैसिव इन्वेस्टमेंट कराने की ओर भारत की सार्वभौमिकता की रक्षा करने के लिये मुल्क को न्यूक्लियर, जो एनर्जी का स्रोत है उसके ऊपर खड़ा करने के लिए इनके अलावा जनता सरकार की कैबिनेट में और कोई भी आदमी नहीं है जो कि ठीक ढंग से इन प्रश्नों पर लड़ सके।

[श्री कल्प नाथ राय]

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि राम नरेश यादव की सरकार यू० पी० में है। जो केन्द्र सरकार होती है वह राज्यों को तेल की अलाटमेंट करती है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान में तेल का कोई संकट नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तेल का संकट क्यों है जबकि केन्द्र सरकार ने तेल का अलाटमेंट विभिन्न प्रांतों को किया है। श्रीमन् मैं यह भी मानता हूँ कि रेलवे बैगनों की कमी के कारण भी हमारे देश में तेल का संकट पैदा हो गया है। तेल की कमी का एक कारण यह भी मालूम पड़ता है कि ईरान के अन्दर गड़बड़ी की स्थिति चल रही है। इसके अलावा कुछ दिन पहले हमारे देश के बन्दरगाहों पर मजदूरों द्वारा हड़ताल की गई। इस कारण से भी तेल और डीजल का संकट पैदा हो गया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि एक तरफ तो इस प्रकार का संकट है और हमारे देश के कुछ भागों में तेल और डीजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कारण है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री कहते हैं कि राजस्थान के अन्दर हम किसानों को ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल दे सकते हैं? मैं साफ तौर पर जानना चाहता हूँ कि जब एक राज्य में डीजल की कमी नहीं है तो क्या कारण हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्दर डीजल और मिट्टी का तेल बिल्कुल नहीं मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की हालत से यह साफ मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को डीजल का जो वितरण किया जाता है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैकमार्केट किया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में निकम्मी सरकारें इस संकट को हल नहीं कर पा रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर किसानों को डीजल नहीं मिला तो वहां पर खेती के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में यह स्थिति हो गई है कि किसान लोग ट्रैक्टरों से अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस ध्यानाकर्षण

प्रस्ताव के माध्यम से मैं केन्द्रीय सरकार से यह मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को फोरन बर्खास्त किया जाये क्योंकि इन राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर मिट्टी के तेल की और डीजल की ब्लैकमार्केटिंग चल रही है। आजमगढ़, गोरखपुर और बलिया आदि स्थानों से हमारे पास पत्र आएं हैं कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर तेल की ब्लैकमार्केटिंग चल रही है और अधिक दाम दे कर जितना तेल चाहे उतना तेल मिल रहा है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने हमारे देश में तेल की आर्टिफिशियल स्केयरसीटी पैदा कर दी है। डीजल के प्राइवेट डीलर्स अपने पास तेल का स्टॉक जमा करते जा रहे हैं और बाद में उसको ब्लैकमार्केट में बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें इतनी निकम्मी हो गई है कि वे इस संकट को हल करने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार इन सरकारों को हटाना नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम मिनिस्टर महोदय से मैं इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि वे पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के माध्यम से और खास तौर पर खेती में ट्रैक्टरों के इस्तेमाल के लिए डीजल के वितरण की व्यवस्था करें। हमारे देश में जो गरीब लोग मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं उनको मिट्टी के तेल का वितरण पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के माध्यम से होना चाहिए। इन चीजों का वितरण प्राइवेट आर्गनस के हाथ में नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान उत्तर प्रदेश के किसानों को जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है उसकी ओर दिलाता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी का तेल और डीजल न मिलने के कारण भारी संकट पैदा हो गया है। सारे नार्थ इंडिया में रबी मौसम की बोआई के लिए कठिनाई पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में इन चीजों के न मिलने के कारण रबी अभियान को

श्री कल्प नाथ राय

जो नुकसान हो रहा है उसको दूर करने के लिए मंत्री महोदय कोई ठोस कार्यवाही करें। हम लोग यहां पर किसानों की तरफ से निवेदन करने के लिए आए हैं, हम कोई शिकायत करने नहीं आए हैं। क्या आप इस संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे ?

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra):

Sir, on a point of order, before the Minister rises to reply. Today is the day for Private Members' Business. But the position as it appears now is that private Members' Resolutions will not. On a Private Members' day all Government business should be suspended, otherwise, we should have started at 2 o'clock itself. If the Calling-Attention goes on till 5 o'clock, Private Members' Resolutions will not be taken up at all. There are very important Resolutions under discussion. I therefore request you to use your discretion and postpone this Calling-Attention to Tuesday and take up Private Members' Resolutions. One Resolution is under discussion and there are two more Resolutions stated. They cannot be ignored. In fact, on a Private Members' day Government business should not be taken up at all, this Calling-Attention should not have been placed for Friday. Private Members' Resolutions do not get any time. If this is the position, then we can as well abolish the day for Private Members' Resolutions and Private Members' Bills. I therefore, request you to give your ruling and agree to the postponement of the Calling-Attention. There is all praise for the Petroleum Minister from the other side and there is not urgency. Sir, I want your ruling.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would only request honourable Members to be brief so that we can go to take up the Non-official Business as early as possible.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर,

माननीय कल्पनाथ जी ने बहुत सारे प्रश्न उठाये हैं जो कि काल-अटेन्शन से सम्बन्धित नहीं हैं। मैं उस के सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा कि तमाम सारी बातों के सम्बन्ध में उनकी धारणा निराधार है जैसा कि अटॉमिक इनर्जी के सिलसिले में इस सरकार की नीति इत्यादि के बावत उन्होंने उठाया है। जहां तक उन्होंने डीजल और केरोसीन की शार्टेज का प्रश्न उठाया है उसके कारणों पर उन्होंने स्वयं प्रकाश डाल दिया है कि किस तरह से यह कमी आई है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति क्या है। उनके पास यह सूचना है कि डीजल पूर्वांचल में नहीं है। मैं एक ही उदाहरण देकर उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। पूर्वांचल में गोरखपुर और बस्ती में जो हमारे डिपो हैं मैंने वहां पता लगाया कि कितना डीजल हमारे डिपो से निकला है। 849 किलो लीटर डीजल उठा है और 1828 किलो लीटर वही स्टॉक में मौजूद है। कमी का कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। हमने प्रदेश सरकारों को लिखा है और डिपो पर अपने कोऑर्डिनेट भी बिठलाये हैं कि वे सप्लाय आफिसर्स के साथ मिलकर इसे वांटने का काम करें। हमारी तरफ से प्रदेश सरकारों से प्रार्थना भी की गई है। हमारे हाथ में अधिकार सिर्फ भ्रजने का है। ब्लैक मार्केटिंग कहां होती है, उसको पकड़ना एसेशियल कमोडिटीज ऐक्ट के मातहत राज्य सरकारों का काम है। यह उनके अधीन आता है वह उसको पकड़ सकते हैं। अगर पेट्रोल पम्प वाले गड़बड़ी करते हैं तो हमने प्रदेश सरकारों से कहा कि वे इसकी शिकायत हमें करें हम उनके लाइसेंस रद्द कर देंगे, कैसिल कर देंगे और किसी दूसरे आदमी को वह काम दे देंगे।

जहां तक पूर्वांचल का सवाल है किसी जगह पर भी कमी डीजल की नहीं है। जहां तक डीजल का प्रश्न है, जहां तक पूरे पश्चिमी इलाके का प्रश्न है चाहे वह राजस्थान

हो, चाहे पंजाब, चाहे हरियाणा हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो, इसको अगर मान्यवर हम देखें पूरे तौर से तो 1977 में हम जितना रोजना देते थे, विक्री हम करते थे, मेरे पास पूरे का पूरा पूरा चार्ट है। वह इतना लम्बा है कि इतना पढ़ना सम्भव नहीं होगा। उदाहरण के लिए दो तीन बातें ही मैं यहां पर देता हूँ। शकूरबस्ती दिल्ली से 1977 में हम 846 किलो लीटर प्रति दिन डीजल बाहर भेजते थे। इस मर्तबा 6 तारीख को हमने 1765 किलो लीटर बाहर भेजा। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की समझ में आ जाय कि इस चीज की कोई कमी नहीं है। जो कमी हुई थी उसको हमने विदेशों से बन्दोबस्त करके पूरा करने की चेष्टा की है और इसमें हमें कामयाबी भी मिली है। और आखिर में सद्-बुद्धि आई है सब तरफ से, पोर्ट की स्ट्राइक जल्दी 12 दिन में खत्म हो गई और वरौनी में भी काम करीब-करीब पूरा आ गया है। इस लिए दिक्कतें कम हो गई हैं।

अम्बाला में 403 किलो लीटर का एवरेज 1977 में था। इस दिसम्बर के महीने में 6 तारीख को हमने 888 किलो लीटर बाहर निकाला है। उसी तरह से हिमालय में 425 किलो लीटर का एवरेज था, 614 किलो लीटर हमने बाहर निकाला है। पूरे हरियाणा में प्रतिदिन 828 का एवरेज था 1502 किलो लीटर एक रोज में पहुंचा रहे हैं। मैं पिछले साल और इस साल का यह एवरेज बता रहा हूँ। इसी तरह से हम लोगों ने पंजाब में और सब जगह पहुंचाया है।

उत्तर प्रदेश के आगरा आदि कुछ स्थानों में कुछ कमी जरूर रही है। उसके कारण से कमी आई है। लेकिन जहां तक पूर्वांचल का प्रश्न है, इलाहाबाद, मुगलसराय, कानपुर, गोरखपुर और बस्ती जो हमारे केन्द्र है जहां से पूरे पूर्वांचल को सप्लाई होता है, उस पूर्वांचल में हमने 2899 किलो लीटर 6 तारीख को रिलीज किया था और 13469 किलो लीटर

वहां हमारे स्टोर में मौजूद है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि अगर यह स्थिति है तो व्यवधान वितरण व्यवस्था में कहां आ रहा है और अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे पास उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का टेलीग्राम भी आया है। मैंने आई० ओ० सी० से कहा है और मान्यवर, मैं करीब-करीब हर चीफ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर और कहीं-कहीं चीफ सेक्रेटरी का भी ध्यान आकृष्ट करता रहा हूँ कि उनके यहां क्या हालत है। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने लिखा है कि हमारे पूर्वांचल में स्थिति ठीक हो गई है। थोड़ी आगरा और सहारनपुर में शिकायत बताई थी। उसको भी पूरा कर दिया गया है। जो हमने पूरा किया है उसको भी मैं बताना चाहता हूँ। हमने कोयाली से, टूंडला से, कानपुर से, सावरमती इस पश्चिमी क्षेत्र के लिए रेलें चलाई हैं। इस और हमारी पूरी कोशिश हो रही है। हम चाहते थे 450 वैनर रोज चला दें और इसलिए चलाना चाहते थे कि अगर देश में कहीं

श्री श्याम लाल यादव : चीफ सेक्रेटरी ने जो लिखा है उसकी सत्यता के लिए कृपया दिल्ली से बनारस जायें। यहा हर पेट्रोल पम्प पर डीजल के लिए ट्रक्टर कारें और ट्रक वालों की सड़कों की संख्या में लाइन लगी रहती है। अभी परसों ही हमने देखा। यह चीफ सेक्रेटरी का जो बयान है यह बिल्कुल झूठ है। वहां के फूड मिनिस्टर ने वहां इस पर राशनिंग लागू कर दिया है पेट्रोल डीजल और केरोसीन आयल पर तो कैसे राशनिंग लागू की है इसको जरा बताइयेगा। चीफ सेक्रेटरी गलत बयान दे रहे हैं।

श्री हमवती नन्दन बहुगुणा : मैं एक बात कह रहा हूँ मैंने बनारस के आपकी फिगर पढ़ कर अभी सुनाये हैं, मैं मुगलसराय के देता हूँ। 597 किलो लीटर 6 तारीख को रिलीज किया 3703 किलो लीटर हमारे डिपोट में मौजूद है। इसका अर्थ है कि वहां जितना

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

चाहिए उस हिसाब से 6 रोज से ऊपर का कवर मुगलसराय में मौजूद है। जो एक स्थिति पैदा हो गयी है जैसे आज एक फोटो छपा है दिल्ली का 5-5 लीटर के नहीं बल्कि गैलन के टिन लेकर लोग करोसीन आयल लेने गये हैं। यह नेचुरल नहीं है मेरी एक प्रार्थना सदन से है कि 24 को यहां एक प्रश्न सदन में आया था अगर रोज आयेगा तो रोज जवाब दूंगा कि एक ऐसा वातावरण बन गया है जिस से एक घबराहट पैदा हो गयी है और उस घबराहट में लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हैं। मान्यवर, एक बात और है कि हमारा महकमा कोयले की कमी को मिट्टी के तेल के जरिए पूरा नहीं कर सकता है। अगर कोयला नहीं है तो मैं उसको पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल के द्वारा उस खपत को पूरा नहीं कर सकता हूं। वह कठिनाई अपनी जगह पर रहेंगी चूँकि सापट कोक नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य श्याम लाल यादव ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनारस फूड डिपार्टमेंट के और हमारे आफिसर की एक ज्वाइंट रिपोर्ट बना कर कल पत्र द्वारा भिजवा दूंगा

(Interruptions)

श्री श्याम लाल यादव : मैंने खुद देखा है रोड्स पर . . .

(Interruptions)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सारे आ-जमगढ़ में अच्छा हाल है। मैं वहां का पता कर दूंगा।

जहां तक माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया है कि आयल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत होना चाहिए मैं कुछ आश्वासन देना चाहता हूं कि 37 रिस्स हैं जो तेल खोजने का काम कर रही हैं? इतनी रिस्स इस देश में इक्वूटी कभी काम नहीं करती रही है और ओ० एन० जी० सी० को 30 फीसदी ज्यादा पैसा आपके सदन ने और उस सदन ने दिया है पहले के

मुकाबले में और वह देते जायेंगे। इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है।

मान्यवर, एक चीज उन्होंने कही है पब्लिक सेक्टर की, इस पब्लिक सेक्टर के ऊपर पूरी बहस तो आप कभी भी कर सकते हैं, मैं, उद्योग मंत्री और सब लोग बयान देंगे लेकिन जहां तक इसका सवाल है तो आयल के क्षेत्र में तो पब्लिक सेक्टर को छोड़ कर कुछ है ही नहीं और हमारी पूरी चेष्टा है कि हम और ज्यादा काम करें। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि वियतनाम के लोग हमसे चाहते हैं कि हम वहां काम करें, तंजानिया के लोग चाहते हैं कि हम वहां काम करें। हमने निश्चय किया है कि जितनी हमारी शक्ति है इसको बढ़ा कर संभव हो तो हम वहां काम करें।

एक चीज और कह कर मान्यवर, मैं समाप्त करूंगा। एक प्रार्थना है कि इस सबके बावजूद जो तेल हमारे पास 6 तारीख को था, 7 तारीख को दिल्ली में 3000 किलो लीटर के दो रेक्स और आये मिट्टी के तेल और एच० एस० डी० के, अम्बाला में 15 सौ किलो लीटर, मेरठ में 15 सौ किलो लीटर, आगरा में 15 सौ किलो लीटर, बरेली में 15 सौ किलो लीटर गया है। केवल 7 तारीख को ही अकेले गया है पटियाला में 15 सौ किलो लीटर गया है, कोटकपुरा, पंजाब में एक जगह है, अमृतसर में, जम्मू में 15 सौ किलो लीटर गया है। यह एक रोज में 7 तारीख को पहुंचा है जो कि 2-3 दिन का कवर है। मेरी एक प्रार्थना है किसान भाइयों से और सवाल करने वालों से कि ईरान की कमी को पूरा करने का बंदोबस्त हमने किया है। 15 लाख टन की कमी नहीं थी बल्कि 1.1 मिलियन टन करीब 11 लाख टन की कमी थी। इसमें से दो लाख टन तो उधर से आ गया और 8 लाख टन हमने बाहर से सामान जैसे ईराक और दूसरे देशों से खरीद लिया है जो कि चल पड़ा है, इस तरह से नवम्बर-दिसम्बर की कमी को पूरा किया है और आने

वाले वर्ष के लिए भी कमी पूरी करने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ईरान के संबंध में अति-शक्ति का को ध्यान में रख कर हम कमी को पूरा करने का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि भविष्य में यह कमियां न आ पायें।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND (Punjab): Sir, I am thankful to the honourable Minister for the statement that he has made. But, first of all, I would like to point out to him one thing. जब आप बात करते हैं तो समझ पड़ता है। परन्तु जब आप पढ़ कर सुनाते हैं तो हमारी समझ में नहीं पड़ता है।

First, Sir, I thought that there was something wrong with my Hindi. But I was following the Hindi of Mr. Kalp Nath Rai and your Hindi also I was following. But the Secretary of yours who wrote this note was only telling this. In this connection. I want to point out, Sir, that there is a proverb in my language:

‘थुक्कां नाल पकौड़े नई पकदे’

And I would add:

‘आंकाड़ां नाल ठिड नई भरदे’

Merely repeating of statistics does not fill the belly. Why am I saying this? I am saying this because when the hon. Minister spoke on the 24th November, he told me that the Punjab Chief Minister said that the picture was very rosy, and that he was also taken in. But since the 24th November, I want to tell him in all honesty things have worsened in the Punjab. I just come to why they have worsened. It is impossible to travel by road in a car because wherever there is a petrol pump, you cannot negotiate the number of trucks and tractors that are standing—so much so that in Haryana, near Kurukshetra there was a road block for more than 8 hours

because no diesel was available and all the tractor-walla as got so angry that they lined up their tractors there on the road. Not only that. I have been sending calling attention motions to the Chairman—I do not have the cuttings with me today—about the price of kerosene. The price of ‘mitti ka tel’ has gone up from Rs. 1.30 a litre to Rs. 2 or Rs. 2.20, but still it is not available. Here I want to say, Sir, that we do not have to go far away. Let the hon. Minister go to the guards standing at his door and ask them. They say that kerosene is not available, soft coke is selling at more than double the price, hard coke is not also available. I know that your Ministry is not concerned with this, but when there is already power shortage, when everybody cannot go in for gas, the only medium of cooking, specially when we have entered the period of deep winter, is either kerosene or coal. And when kerosene and coal are simultaneously missing, you can understand what the situation is.

I would not go on reading from newspaper cuttings of the last three days about the situation in Delhi. The National Herald, the Hindustan Times and the Indian Express, all talk of the worst crisis in the capital city in history. Now, Sir, the hon. Minister has talked about the north-western region—Uttar Pradesh, Delhi and Punjab. But Bhopal is not a part of the north-western region. I am quoting from the Hindustan Times: Diesel shortage in Bhopal is of a terrific nature. I want to ask the hon. Minister: Is he aware that up to Rs. 150 crores worth of crops will be lost, because diesel was not available in Haryana and Punjab alone? Is he aware of this? Despite all the efforts made by him, and all the rosy picture that was depicted by the Punjab Minister the other day, the shortage continues to be acute and in such a period, the sowing period, already foodgrains worth Rs. 150 crores are lost, because they have not been able to sell them in time.

[Shri Jagjit Singh Anand]

Sir, then I want to ask him specially about Delhi itself. According to the Hindustan Times of 7th December:

'Half a day stock of kerosene is available;

No stock of coal;

Situation is grim'.

K. N. Sahni said:

'If go-slow in Barauni does not end, situation will be worse'.

This is yesterday's 'Hindustan Times' I am quoting: M. L. Khurana dashes three times from here to Calcutta for coal and kerosene. I do not know what kerosene has to do with Calcutta coal definitely has to do with it. But I am only quoting from the paper. Maybe, kerosene has also got to do something with Calcutta. I am not aware of that.

Then, Sir: Kerosene to be rationed in Delhi; 4-unit cards will get 4 litres of kerosene per fortnight. A train of 2000 kilo litres was to arrive. He was giving some figures. Sir, the trouble is so serious. There are queues and queues, specially in trans-Jamuna areas, people go on standing for hours and hours, people have gone from place to place, house-wives have gone from place to place, in trans-Jamuna areas, for a bottle of kerosene. Then, Sir, the proper size of the bottle is not being given. Bottles are being substituted so that they are not 650 mm. Then, Sir, I want to ask from Mr. Bahuguna: Is he aware that roaring black-marketing is going on in Delhi? Does it have something to do with the colour of the Delhi Administration, because the people who indulged in black-marketing in kerosene and coal, *voh samajhte the*:

संसा भये कोतवाल अब डर काहे का ।

Those who have come to control the Delhi Administration, are notorious; they have been blackmarketeers of the country for the last three decades. When they are controlling it, why

bother about black-market? Is it because this can be one of the factors? It is good that he has clarified later on that the .8 million tonnes of loss that was there from Iran is being made good elsewhere because I am all for figures going out from this House which will encourage the situation. One reason for this scarcity that has been created is because the people are not sure of the morrow. Now he has said that he has arranged .8 million tonnes from Iraq. He did not say so originally. He should keep back anything that would lead to any sort of misgivings among the people. The situation is going to be worse because that job is being done very well by Shri Kidar Nath Sahni and by Shri Madan Lal Khurana who is rushing to Calcutta. Shri Bahuguna should leave it. Though he is in uncomfortable company, he should leave the scarcity mongering which the Delhi Administration has done. Lastly I would ask him whether, despite all the feeding that he is doing in this matter, does he not think that the distribution system is a total failure? Does he not think that something more has to be done? He was quoting Ambala, Sakur Basti and Amritsar. When more than double is being brought in, what is this scarcity due to? Though it does not concern his Ministry, it concerns his Government. Very severe measures will have to be taken to take away this job of kerosene distribution from those who indulge in black-marketing. This black-marketing has been there for almost two weeks. How many kerosene dealers have been punished? How many licences of kerosene dealers have been cancelled? How many licences of coal depot holders have been cancelled? How many people have been brought to book? Has anybody been put inside the jail for this? They are just playing with the lives of the people. I would request him to enlighten me on these things. I would be very thankful to him.

SHRI H. N. BAHUGUNA: Sir, it is very difficult to take the responsibility

of the State Governments on my shoulders. It would also be unfair for me to endorse some comments made by the hon. Member with regard to the State Governments, not because of anything but because of the fact that it would be unfair for anyone to prejudge the issue or judge people without hearing them as to what they have to say. The hard fact of life is that due to unfortunate and unprecedented floods, coal mines have just stopped working. They cannot work. No coal can come out. They are flooded. I cannot speak on behalf of the Minister of Energy. I have no authority to do it. But it is a hard fact that soft coke is not available in the country and this country does not have the capacity to substitute kerosene oil for soft coke, whosoever may be the Minister including Mr. Anand. I am willing to surrender my portfolio to him if he can manage it better and if he can substitute kerosene oil for soft coke, I will be very very happy. Sir, even without surrendering to him the portfolio, I am willing to sit with him in my office and take any decision that we can legally take to set the matter right. I am willing to seek his assistance because as far as I am concerned, I have done my best. Kerosene oil distribution is not my business. It is the business of the State Governments. We give them certain quota. They give the licences. People deal in kerosene oil on the basis of these licences. They are entitled to cancel the licences if there is black-marketing. The pictures in the Hindustan Times and elsewhere are not of people with a bottle. It is of people with drums. You can see the picture.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: It is not for kerosene oil. It is for diesel. I agree with you about diesel.

SHRI H. N. BAHUGUNA: I am talking about kerosene shortage photographs in Hindustan Times. They are there. You can see the

photos. They are not photos of people with bottles in hand. They are drums. I am not saying that there is no shortage. It is very short because soft coke is not available. Now, compared to last year's supply we have tried to stretch ourselves too far in providing them with a little more. So far as diesel is concerned, I am willing to go round with my hon. friends, Shri Jagjit Singh Anand and Shri Kalp Nath Rai. We will arrange their trip tomorrow to go round the depots in eight or ten places in Delhi, Punjab and Haryana and they can see for themselves whether what I am saying is correct or not. All we have done is to despatch these things. It is true that in between on some days, there has been some slippage, and there has been a scare outside. And because of those earlier incidents, there has been a scare outside. Our peasants are very intelligent. And our Radio carries every story correctly. The Radio says, बन्द्वी मे हडनाल तेल बन्द हो गया the Radio says, "Go slow in Barauni" तेल नहीं भेजा है। इरान में गगवड है, तेल नहीं आ रहा है।

And the peasantry feels what is going to happen if the rains fail in January, and what is going to happen for the thrashing season. Some of these people are really scared and, therefore, there is a scare purchase in the market.

SHRI KALP NATH RAI: It is psychological.

SHRI H. N. BAHUGUNA: It is psychological. I would appeal to this House and hon. Members like Mr. Anand who have a lot of public influence, and like Mr. Kalp Nath Rai, who comes from a great area—Azamgarh—and where he has got a great influence, to exercise their sobre influence on the people there and to request them to bear with us, and at the appropriate time nothing will really trouble them if only they would bear with us and purchase only their day-to-day needs.

[SHRI H. N. BAHUGUNA]

Sir, the hon. Member asked me as to how many licence of the shops have been cancelled and how many blackmarketeers have been arrested. Sir, as I told the House earlier, I have sent, in my personal name, a request to all the Chief Ministers and the Officers concerned, like the Lieutenant Governor of Delhi also, requesting them to see that they must take very stringent action for any violation.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Thank you for this.

SHRI H. N. BAHUGUNA: I personally communicated to them. But I have no field agency whatsoever except those few officers. For example, Sir, nobody knows it better than you that the Hindustan Petroleum has a little office in Lucknow looking after a vast area. So, if I were to tell that one man to look after the wrong things in Varanasi, that is not possible. That is why the powers are available with the State Governments and they are expected on behalf of the Government of India also to exercise them...

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: They are the leaky State Governments and so the pipeline of oil does not reach the people.

SHRI H. N. BAHUGUNA: ... to curb these things. But certainly I must say at this point of time that I will be failing in my duty if I were not to be grateful to these State Governments—Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Delhi. They have tried to do their best. But I hope that with their co-operation and with the co-operation of the House, it is still better for us to do things.

[The Vice-Chairman (Shri Shyamlal Yadav) in the Chair.]

Sir, as far as figures are concerned, I may repeat again that in Delhi itself yesterday we have given twice the amount of diesel than we gave last year for the whole month of December on an average. So, what I am

trying to say is that really this scare purchase has got to be stopped.

Sir, I plead with the House and with the people at large to bear with us and try to understand, and that Iran's problem has been solved and I make a declaration that even for the new year, we have already taken steps—which I do not want to disclose right now—to see that the through-put, that is the crude purchases from outside, does not fall short of our total requirements. We propose to import this year about 16 million tonnes. We want to be very sure and absolutely sure.

Sir, Mr. Kalp Nath Rai had raised a point and I forgot to answer it at that point of time. We will be producing this year 12 million tonnes as against 9.00 and odd millions which we were producing the day I took over. It is not that I have found new wells. Maybe, in a couple of days, I have to give some good information to this or that House about the new finds because everyday I am expecting some information or the other in view of the large degree of effort that is being made at onshore and offshore to find new sources of crude oil.

श्री निच चन्द्र झा (बिहार) : उपसभा-ध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उस में करीब-करीब बहुत राज्यों की जो परिस्थिति है उसके बारे में उन्होंने कहा लेकिन जहां तक मैं सुन सका, बिहार के बारे में शायद नहीं कहा। बिहार की परिस्थिति चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उससे भी खराब है और केरोसीन आयल की कमी हमेशा वहां रहती ही है बावजूद बरौनी रिफाइनरी और बड़ी रिफाइनरी आपने वहां स्थापित कर दी। लेकिन वहां की हालत बदतर ही रहती है और बड़ी हैरानी होती है कि जब आपने जवाब दिया कि हमते ल में इतना

इंवेस्टमेंट कर रहे हैं, तनजानिया हमको बुला रहा है, वियतनाम हमको बुला रहा है, हमारे यहां तब भी तेल की कमी हो जाए तो यह चिन्ता का विषय हो जाता है और सोचने का विषय हो जाता है। साधारण आदमी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जरूरत की चीज तेल हो जाती है, कम से कम घर में चिराग जले, रोशनी हो यह बहुत जरूरी है। अब मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि पहली बात जो आपकी आयल रिफाइनरीज हैं, चाहे बरौनी हो, चाहे कहीं हो, अभी अहमदाबाद भी आप गये थे उद्घाटन करने, मैं भी अहमदाबाद में था...

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) :
आप गये नहीं थे उद्घाटन में।

श्री शिव चन्द्र झा : हम लोग दूसरे ही काम में लगे हुए थे और हमने देखा कि यह भी बन रहा है, अच्छी बात है, रिफाइनरी खोली जा रही है। जहां भी रिफाइनरीज हैं क्या यह बात सही है कि वे फुल कैपेसिटी पर काम नहीं करती हैं। प्रोडक्शन की जितनी क्षमता है उनके मुताबिक कारखानों में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्या यह बात सही है? बरौनी को खासकर मद्देनज़र रखते हुए हमें बतायें कि कैपेसिटी के मुताबिक वहां प्रोडक्शन क्यों नहीं होता है? यह मेरा पहला सवाल है।

दूसरा सवाल है, सारे देश में कुल कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं और पर-कैपिटा कंजम्प्शन क्या है मोटे पौर पर, पापुलेशन जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी? उमकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बाहर से कितना तेल आता है, आप कितना अपने प्रोडक्शन से मीट करते हैं और कितना डैफिसिट होता है और इसको आप इंडिजिनस प्रोडक्शन से कैसे पूरा करेंगे? इसकी योजना आप रखते हैं या नहीं। कहने का मतलब यह है कि तेल के मामले में हम कितने दिन बाद ही सही, सैल्फ-सफिशियेंट होने जा रहे हैं या नहीं? ऐसी कोई योजना है तो वह हमको बतायें।

तीसरा सवाल है कि आपने कहा कि पब्लिक सैक्टर कमज़ोर नहीं हो रहा है। बाबू साहब कहते हैं कि पब्लिक सैक्टर खत्म करेंगे। लेकिन वह कोई नहीं करेगा। प्राइवेट सैक्टर खत्म हो जाएगा, पब्लिक सैक्टर खत्म नहीं होगा। यह समाज का तकाज़ा है। विदेशी तेल कंपनियां देश में किसी न कसी रूप में काम कर रही हैं चाहे सरकारी लेवल पर एग्रीमेंट हो, चाहे प्राइवेट लेवल पर। तो ये कंपनियां देश में से कितना रुपया रायल्टी के रूप में ले जाती हैं, यह हमको बतायें। . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) :
विषयान्तर मत हो जायें। . . .

श्री रोशन लाल (हिमाचल प्रदेश) :
यह सप्लाई और डिमांड का सवाल है, आपने इकानामी को ले लिया, तेल कंपनियों की बात पर ख़ामख़वाह बात जाया करेंगे। हम भी किसी स्टेट से आये हैं।

श्री शिव चन्द्र झा : तीसरा सवाल है कि इनको रायल्टी में कितना प्रतिशत मिलता है, यह हमको बताइये।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) :
विषयान्तर हो जाएगा।

(Interruptions)

श्री शिव चन्द्र झा : कैसे हो जाएगा? यह किसी न किसी रूप में यहां से ले जाते हैं। हम उनको कितना देते हैं, कितना यहां से वह ले जाते हैं। यह बताइये। यह मामूली 4-00 PM बात नहीं है, सोशल बात हो जाती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिये और ब्लैक मार्किटिंग के लिये बहुत सी बातें आईं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी योजना है आपके पास जिससे इसे स्ट्रिम लाइन किया जा सके। मैं यह नहीं कहता कि डिस्ट्रीब्यूशन को सरकार अपने हाथ में ले ले।

श्री हेमवती नन्दन बहगुणा : मान्यवर, जो हमारे तेल शोधक कारखाने है उनकी क्षमता 29 मिलियन मीट्रिक टन तेल शोध करने की है। सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जो हल्दिया में लगा हुआ है। जहां हमारी रिफाइनरीज हैं, वहां पूरी क्षमता में हमारी रिफाइनरीज का करती हैं, तेल शोधक कारखाने काम करते हैं, कुछ स्टेशनों पर ब्रेक डाउन या श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच में कुछ आपत्तिजनक स्थिति पैदा हो जाती है इसको छोड़ कर। पारसाल, जो गुजिश्ता साल गया 1977-78 का उसमें हमारे देश की रिफाइनरीज ने जितना तेल शोधना था, करीब-करीब 24 मिलियन मीट्रिक टन जो हमारे देश की आवश्यकता थी, उसका शोधन किया। इस साल 26 मिलियन मीट्रिक टन शोधन की संभावना है। इसलिये यह कहना कि रिफाइनरीज पूरा काम नहीं करती हैं वह पार्श्वी तो सही है। उदाहरण के लिये जैसे बिहार प्रदेश है जहां से माननीय सदस्य झा साहब आते हैं वहां जून, 1978 से लेकर नवम्बर की 30 तारीख तक श्रमिकों और प्रबन्धकों के झगड़े के कारण, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता कुछ सुधार किया गया है, 3 लाख 50 हजार मीट्रिक टन की हानि हुई और हम कुछ नहीं कर सके। जाहिर है कि श्रमिकों को शायद वार्तालाप के कारण मामला तय करना था और कुछ मामला तय भी किया गया है। अभी भी वार्तालाप चल रही है।

माननीय झा साहब ने प्रश्न उठाया कि हम सेल्फ सफिशिएंट कब होंगे, कब आत्मनिर्भर होंगे? मैं इसके लिये पूरी चेष्टा कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि 37 रिस् इस वक्त खुदाई का काम कर रही है। 25 हजार आयल नेचुरल गैस कमीशन के श्रमिक जिनमें चार हजार के ऊपर वैज्ञानिक हैं, सब मिल कर टोह में हैं और जगह-जगह तरह-तरह का काम कर रहे हैं। तेल

निकालने का काम कर रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है, सौभाग्य भी है कि सन् 1951 तक विदेशी तेल कंपनियां खासकर अमेरिका की तेल कंपनी भारत को कहती थी कि भारत में तेल मिलेगा ही नहीं इसलिये बूढ़ो मत। मगर जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता के कारण और उनकी समझदारी के कारण यह संभव हुआ कि हमने रूस के साथ वार्तालाप की और रूस ने हमारी मदद शुरू की। हमको उनके कारण तेल मिलना शुरू हुआ अखलेश्वर से। पहले हम को डिगबोई से बहुत थोड़ा तेल मिलता था। हम तेल खोजने के लिये कम्बे बेसियन गुजरात की तरफ आगे बढ़े और तब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन भाग्य ने पूरा साथ नहीं दिया। 28 वर्ष हो गये कुल जमा हमारे देश में साढ़े 10 मिलियन टन तेल पैदा करने की क्षमता प्रति वर्ष है। लेकिन हम उतने भाग्यवान नहीं जितना कि चाइना निकला। चाइना ने भी करीब-करीब हमारे समय से ही यह काम शुरू किया था। अब चाइना की क्षमता हो गई है चार सौ लिमियन टन प्रतिवर्ष। क्षमता योग्यता के कारण नहीं हुई है क्षमता धरती में सुराख करके तेल निकालने से हुई है। तेल का भंडार मिला है उससे क्षमता बढ़ी है। सुराख कई जगह किये गये हैं और अब ज्वालामुखी में सुराख हो रहे हैं 1958 से लेकर अब तक सुराख हो रहे हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है कि कहां गैस है और कहां तेल है। हमने अभी आशा नहीं छोड़ी है, काम चालू है, आत्मनिर्भरता के संबंध में इस चेष्टावान है। कब तेल मिलेगा, कब तेल के भंडार मिलेंगे यह तो भाग्य पर निर्भर करता है। कहां से कितना तेल मिलेगा, 100 मिलियन टन तेल मिलेगा या 50 मिलियन टन तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे लिये यह कहना संभव नहीं है। फिर भी आत्मनिर्भरता की तरफ हमारे प्रयास जारी है। आत्मनिर्भरता की तरफ हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे और पैसे की कमी के कारण इसको रोकेंगे नहीं।

तीसरी बात इन्होंने यह कही कि विदेशी कपनियां किसी न किसी रूप में किसी न किसी शक्ल में यहां मौजूद हैं। सब जानते हैं कि आयल इंडिया में 50 फीसदी, बरतानिया की एक कंपनी है उसके हिस्से मौजूद है। असम आयल इंडिया उनकी है, वहां तक वह मौजूद है। कुछ लुवरजोल और कुछ ल्यूब बनाने का काम एक-आध कपनियां करती हैं लेकिन और किसी रूप में न तो उत्पादन और न वितरण में इनका हाथ है। विदेशी कपनियों का तेल उत्पादन में सहयोग हम को जरूर चाहिये। बहुत से कंटेक्टर हम को जरूर चाहिये वाम्बे हाई में काम करने के लिये। देशी और विदेशी दोनों उसमें आते हैं; क्योंकि पूरी क्षमता और योग्यता भारत की उस संबंध में पूरी नहीं हो रही है, इसलिये इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक बात उन्होंने रायल्टी के बारे में कही है, इसके आंकड़े तो इस वक्त मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भारत की तेल की नीति के परिणाम-स्वरूप और इस देश की अर्थ व्यवस्था के ढाँचे में पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूर-दृष्टि के कारण आज हमारा देश संसार में तेल के मामलों में आठ देशों में से एक है। तेल पैदा करने वाले देशों में हमारी योग्यता बराबर बढ़ती जा रही है। विदेशी लोग हम से तेल नहीं मांग रहे हैं बल्कि वे तेल निकालने में हमसे मदद चाहते हैं। वियतनाम चाहता है कि हम उनको तेल निकालने में मदद करें। तम्जोनिया चाहता है कि हम उनको तेल निकालने में मदद करें। हमारे पास तेल निकालने की योग्यता और क्षमता है। हमारे देश में तेल को खोज का काम चल रहा है और हम आशा करते हैं कि यह कदम हमें आत्म-निर्भर की ओर ले जाएगा।

माननीय सदस्य ने बिहार का प्रश्न उठाया। बिहार सरकार की तरफ से हमारे पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। यह बात ठीक है कि बरौनी में तेल कम निकालने के कारण वहां की पाइप लाइन बन्द हो गई

थी, लेकिन पटना डिपो को हमने तेल भेजना बंद नहीं किया। बिहार के लिए जितनी खपत हो सकती थी वह तेल उनको मिलता रहा है। अब तो बरौनी में भी तेल बनना शुरू हो गया है। वहां पर 9 हजार टन तेल बनाने की क्षमता है, लेकिन अभी आठ या साढ़े आठ हजार टन तेल निकालने की आशा है। बरौनी के कुछ लोग आज सुबे 10 बजे मिले हैं। उनसे वार्तालाप चल रहा है। वहां की तीन यूनियनों के लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। उन्होंने वहां पर कुछ कमियां बताई हैं। उनसे हमारा वार्तालाप अभी चल रहा है। बिहार के संबंध में कोई विवरण हम इसलिये नहीं दे पाये हैं कि वहां की सरकार की तरफ से हमारे पास कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य झा साहब ने वितरण की बात कही है। मैं एक पत्र के साथ उन्हें लिख कर भेज दूंगा कि बिहार की स्थिति किस प्रकार की है और कहां-कहां बिहार में हमने तेल भेजा है।

SHRI AMARJIT KAUR (Punjab):
Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to invite the attention of the hon. Minister to the news item which appeared in 'Hindustan Times' on the 6th of this month under the heading "Shortage of diesel hits agriculturists in Punjab". It says:

"The current diesel shortage has hit mechanised farming in Punjab. Panic-stricken farmers queue up daily with their can at the nearest petrol pumps. Despite claims by the authorities that there has been substantial improvement in diesel supplies, for the last one week, queues have lengthened rather than become shorter. In a number of areas, rabi sowing has been adversely affected by the diesel shortage. The production target is not likely to be achieved because of the untimely sowing and watering. Punjab's rural scene today presents a dismal picture. Thousands of trucks and tractors can be seen lined up in front of the diesel pumps

[Shri Amarjit Kaur]

creating traffic dislocation. Transportation of goods has also suffered because of the immobilisation of the trucks."

It has also been stated:

"The shortage of kerosene oil was due to the diversion of wagons for diesel. The demand per day was 400 Kl. Soft coke supply also had been inadequate."

Sir, is the Government aware that 95 per cent of the farmers of Punjab and Haryana are in acute debt to the nationalised and co-operative banks because of their total dependence on these institutions for their key inputs and for the mechanisation of their farm lands? These farmers had, in the very near past, been devastated by floods and hailstorms and were, therefore, unable to pay back their debts to these banks. These farmers are also to depend entirely on the Central and the State Governments for the free flow of diesel oil so that they could run their diesel pumpsets and tractors so that they could, at least this time, pay back these high interest loans they had taken from these banks?

Now that diesel oil has not reached the intensively progressive agricultural areas in time, the sowing of crops has become unremuneratively late and crops already sown, which are dependent on diesel run pump sets, are withering away due to the non-availability of diesel. Because of these reasons the prospects of these poor, yet progressive farmers of paying back their input debts to these 'hard-hearted' banks has become more or less impossible again.

Under the circumstances, why did the Government not anticipate this impending shortage of diesel and kerosene and prepare in advance for this contingency to save the farmers and the town folk this harassment they are suffering today? What

is the intention of the Central Government in giving debt relief to these unfortunate farmers and what planning is being done to see that the shortage of these essential commodities of diesel and kerosene never occur in future—due to any circumstance—especially during sowing periods in this country?

Would the Government not think of creating a corporation for the supply of farm inputs to the farmers, thus assuring the farmer a stable future, and not let the future of the farmers economy be reduced into a gamble?

SHRI H. N. BAHUGUNA: Sir, I disagree with the entire story carried by the Hindustan Times, in the sense that it is a total travesty of truth to say that adequate precautions or measures were not taken. If the hon. lady Member had seen my statement on the 24th November in this House, she would have seen that with the installation of the Janata Government we foresaw and we went into the question of storage capacity in this very high mechanised agriculture-prone area and we decided to expand the storage capacity by 20,000 Kls. during the last one year. That was forestalling the situation. Of course, this capacity will be in operation by December, 1978 but we did store there 1,62,000 Kls. by the end of 30th September, 1978, in the hope that this will be available to us when the sowing season comes in November etc. Unfortunately, due to the Bombay Port Trust strike of 45 days, about 75,000 tonnes had to be depleted from out of this stock for non-movement of this commodity from that particular area. Now, the hon. lady Member wants me to assure the House that under no circumstances shall there be shortage. There are factors beyond the control of the Government. The only thing to be seen is whether the Government has been fairly conscious about the needs of the farmers. I am sorry to say that I have no such failure to my notice in which the Government of India could be taken to task for not being able to foresee the situation.

Then the hon. lady Member has said that there was a diesel shortage in Punjab. I have already said that in Punjab in the month of November we moved 17 per cent more diesel than we did in 1977. Obviously, the requirement of the farmers has been more than this. Normally the growth rate would be about 9 per cent but we gave them 17 per cent more than the last year. But it is true that the Punjab farmer is a very progressive farmer, very-well informed farmer.

Now, Sir, the only trouble is that everybody thought that we are going to collapse for the reason of non-availability of Iran oil. Therefore, there have been scarce purchase and I know some friends in Punjab. The hon. lady Member would come to know about it if she talked to some of those people who have already stored diesel oil for thrashing season even from now. Therefore, there has been some difficulty. I would again plead with the hon. lady Member to use her influence with the people to help us in this difficulty which we are foreseeing for factors beyond our control.

*SHRI E. R. KRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, even though the strike at Bombay Port has been settled peacefully, yet I find no import of oil as expected, has taken place so far and there is still a great shortage of Kerosene, Diesel oil and fertilizers.

The Hon'ble Minister Shri H. N. Bahuguna had promised to take three steps on 24-11-78. I would like to know from the Hon'ble Minister as to what steps have been taken in this matter. He had also promised that he would procure about 500,000 tonnes of crude in lieu of the expected shortfall in supplies from Iran. He had also informed this House for arranging 300,000 tonnes of diesel and other petroleum products from friendly

countries. Had he kept the promise there would not have been any deficit of Kerosene etc. as witnessed today.

There is a front page news today in 'The Hindustan Times' depicting the sufferings of people in Delhi. The Hon'ble Minister has just informed this House that the people were unnecessarily scared on the basis of newspaper reports and started hoarding Kerosene more than their actual requirement.

I may tell the Hon'ble Minister, it is natural for the people to purchase anything more than they needed, whenever there is a scarcity in the market. If there is a shortage of sugar, it is but natural, that the people would purchase 10 K.G. of sugar when they actually need only 5 K.G. Since the Government proclaims now and then that they are here for the poor people, it is their bounden duty to provide the essential commodities to the poor people at reasonable rates. I hope, the Minister will take necessary steps to protect the interest of poor people and keep up the supply of essential commodities.

Thank you.

SHRI H. N. BAHUGUNA: Sir, I am grateful to the hon. Member for reminding me of the needful to be done. I want to correct two things in his statement. Firstly, I never said that we are short of 30 lakh tonnes of products. I had merely said that day that 3 lakh tonnes had been confirmed from outside. It was not 30 lakhs but 3 lakhs. Today, between the 24th and today, the position is that we have a total of 4.18 lakh tonnes of these products, i.e., 1.18 lakh tonnes more. It consists of 1.10 tonnes of diesel, 88,000 tonnes of kerosene, 200,000 tonnes of furnace oil and 20,000 tonnes of naphtha. All these shall be able to meet the shortages which occurred, as I said earlier, due to our Brauni problem where we lost 3.5 lakh tonnes of the total product, and also some shortage of crude which we expected from Iran. All that is being covered up. I have indicated the action that we have taken. He has talked about

*English translation of speech delivered in Tamil.

[Shri H. N. Bahuguna]

the photographs in Hindustan Times I have no objection to people purchasing 10 litres. I only want to plead that the House should bear with me when I say that kerosene oil in India is not available in a quantity which will be a total substitute for soft coke or for other fuels. Therefore, Sir, this shortage is there in spite of higher allocations of kerosene oil to Delhi State. It is not because of us. It is because of a situation beyond our control which again is because of unprecedented floods in the coal mine areas.

श्री रोशन लाल : काबिले एहतराम वजीरे मासूफ पेट्रोलियम, कमिश्नर ने अभी फरमाया और आदोशुमार पेश किये इस हाउस में कि इतना डीजल और तेल मैंने पंजाब को दिया, इतना इस जगह को दिया, इतना फलां जगह को दिया, पर हर चीज के दो पहलू होते हैं और उन पर पहलू पर गौर करने के बाद उन नतीजे पर आदमी पहुंचता है कि जैसे कि आबादी लगातार बढ़ रही है उसी तरह ही बिजनेस कम्यूनिटी या प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी आज इण्डस्ट्री जो है वह ट्रान्सपोर्ट इण्डस्ट्री है। लोगों के पास ट्रक्स, बसेज और ट्रैक्टर जमींदार के पास पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर जब आप उन एदादो शुआर को देखते हैं जो आपने साले गुजस्ता के या इससे पहले जब आप उनके साथ आज मुकाबले करते हैं तो आपको यह चीज भी ध्यान में रखनी चाहिय कि ट्रान्सपोर्ट की इण्डस्ट्री भी बढ़ती जा रही है। इसलिये खपत भी ज्यादा है, सोराफीन की मांग भी ज्यादा है। इस चीज से आप इन्कार नहीं करेंगे। जहां तक मिट्टी के तेल का सवाल है यह वह गरीब तबका जो मजदूर है या छोटा क्लर्क वगैरह है वह किरोसिन आयाल खास कर वे खर्च करते हैं, जिसके पास गैस का इन्तजाम नहीं है और न ही यहां आपके पास ईंधन है

कोयला है लकड़ी जलाने की नायाब है। तो इस सूरत में आपको बड़े शहरों में खास करके दिल्ली जैसी जगह पर खुद मैंने यह चीजें डिपो पर जाकर अपने आप देखी हैं कि साऊथ दिल्ली में जहां मैं रहता हूं तेल के लिये तीन दिन से लाइनें लगी हुई थीं। मैं भी अपने नौकर को लेकर गया था। चार-चार, पांच-पांच लिटर तेल मिल रहा था। लेकिन कुछ को तेल मिला, कुछ को नहीं मिला। वे लोग वहां से वापिस दूसरे डिपो पर चले गये। मैंने पूछा कहाँ जाओगे तो उन्होंने कहा कहीं और जायेंगे।

लेकिन एक चीज जो मैंने पहले भी और कुछ मेरे फाजिल दोस्तों ने पहले भी आपके सामने यहां उठाई कि आपकी तकसीम का जो सिस्टम है वह बड़ा नाखिस है। उसके लिये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आपका जितना भी तकसीम का सिस्टम है उसकी चैकिंग भी प्रापली की जाए तो डीजल या किरोसिन की कमी जो आपके सामने हरेक मम्बर यहां आकर बतलाता है वह महसूस नहीं होगी। उसका कारण यह है कि मैं एक जगह खड़ा था। एक आदमी ने पूछा कि तेल है। उसे इन्कार कर दिया गया और कहा गया, तुम पिछले रास्ते से अपना तेल छोड़ जाओ जब वह अपना तेल पिछले रास्ते से छोड़ गया, ही गाट दि आयाल। तो आपका जो डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, उसमें जब आप कौन सी मोमेंट काटते हैं वह भी चैक करें। डीजल के बारे में एक मोहतारिमा पंजाब की लेडी मम्बर बोल रही थीं और मैं भी पंजाब में रह कर आया हूं, मुझे 1975 में गुरु तेग बहादुर जी का जन्म-दिन मनाने के लिये एक मुकाम कर बुलाया गया और मैं देहात में एक बड़े जमींदार के घर जब गया तो मैंने पांच बड़े बिग बैरल डिजल आयाल के उनके घर में देखे। तेल की बड़ी किल्लत थी उन दिनों। मैंने उनसे यहां दो ट्रैक्टर भी खड़े थे। मैंने खाना भी वहीं खाया। तो मैंने जब देखा कि तेल की

कमी है तो उनसे पूछा कि तुमने इतना तेल क्यों इकट्ठा किया है। तो एक तरफ जमींदार अपनी डिमाण्ड से ज्यादा स्टोर कर लेता है ...

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) :
मुख्तसार में सवाल पूछिये।

श्री रोशन लाल : मैं खत्म कर रहा हूँ। एक और चीज है कि जब आजकल रबी सोइंग सीजन आ रहा है तो उसके साथ ही बड़ा जमींदार, बड़ा लैण्डलार्ड, बड़ा जागी दार, बड़ा बिस्त्रेदार अपनी देने वाली रबी की क्रापा है, उसकी प्राइस भी फिक्स करवाने पर जोर देते हैं। यह चीज कह करके कि तेल की शार्टेज है, मुल्क में तबाही आ जायेगी, इतनी हम गन्दम नहीं बो सकेंगे जिसका नतीजा है कि जो मुअर क्लास, कन्ज्यूमर्स हैं, मुलाजमीन हैं मुल्क के, देश में वे सफर करते हैं। यह पहलू भी ध्यान में रखना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) :
मुख्तसार में कहिए।

श्री रोशन लाल : एक है शार्टेज और दूसरे तकसीम का इन्तजाम नाखिस है। इसका दूसरा पहलू यह है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं उनको चीजें नहीं मिलती। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या इस सिस्टम को तबदील करेंगे, चेंकिंग करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश में आता हूँ। मैं हर साल गमियों में वहां जाता हूँ। वहां गैस की कोई एजेंसी नहीं है, लोगों के पास जो तेल के डिपो हैं, वहां तकसीम का इन्तजाम सही नहीं है, ब्लैक मार्केट बड़े जोरों पर है। मुझे बेशक तेल एक डिपो से नहीं दूसरे डिपो से मिल जाता है। बहरहाल, जिस तरह से कि आपने कहा कि यह मेरा सब्जेक्ट नहीं यह स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपकी मशीनरी ठीक से काम नहीं करती और स्टेट्स चेंकिंग नहीं करते तो उसके लिए

गरीब लोग क्यों सफर करें? जब आज 2२०, 3२०, 4२० में तेल का बोतल बिकता है, खास कर इंडीरियर में, तो आप अंदाजा लगाइए गरीब लोगों की क्या हालत हो रही होगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) :
अब कृपया समाप्त करिए। अब कोई प्रश्न बाकी नहीं रह गया है।

SHRI ROSHAN LAL: Thank you Sir, I have completed.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मोहतरिम सदर साहब, मैं आप की इजाजत से एक बात अर्ज किया चाहता हूँ कि जो मेम्बर साहब ने सवाल उठाए हैं और जो कुछ उन्होंने खयाल करा है बड़े किसानों को और छोटे किसानों को लेकर, मैं उनसे सौ फी सदी एक राय हूँ और इस देश का एक बड़ा सवाल यह है कि गांवों के अंदर जो 13 फी सदी लोगों ने 80 फी सदी दौलत पकड़ कर रखी है, उस 30 फी सदी का कुछ इंतजाम करना होगा। ये किसान के नाम पर भाग जाते हैं और किसान के नाम पर 30 फी सदी लूट कर रहे हैं। उससे हम उनको बचा सकें इसके लिए सब की मदद जरूरी है। इसके लिए जरूरत है कि हमारे आन्दोलन मेम्बर ऐसे बड़े किसानों के घर खाना न खाएं। ...

(Interruptions)

डा० रफीक जकरिया (महाराष्ट्र) :
आप नहीं खाते क्या ?

श्री रोशन लाल : वह भी डिनर खाते हैं जो आपके इर्द-गिर्द बैठे हुए हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता हूँ, इस्तदुआ कर सकता है ? और मेरी दूसरी इस्तदुआ यह है कि जो बंटवारे का काम है, मैं इस हाउस के अन्दर

[श्री हेमवी नन्दन बहुगुणा]

जो ख्यालात का इजहार किया गया है इसको मद्देनजर रखते हुए सूबे के वफ़ीरे आला लोगों को खत लिखूंगा और उनसे भी इस्तदुआ करूंगा कि वे इस नज़रिए से सारे सवाल को देख कर बंदोबस्त करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): That has been covered. Let us go to the next item.

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab): My name is there. I want to ask a question.

SHRI S. W. DHABE: Please allow her to ask a question. You have allowed two Members from the Congress (I).

SHRI H. N. BAHUGUNA: It is not a question of 'I' or 'R'. It is a national question.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): That is not the rule.

SHRI S. W. DHABE: Let her ask one question. What is there?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): No. We have already taken a lot of time. Every point, every aspect has been covered.

DR. RAFIQ ZAKARIA: The Minister is ready to reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): No.

DR. RAFIQ ZAKARIA: Why are you so rigid when the Minister is prepared to reply?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): I am not rigid, I am not rigid.

SHRI S. W. DHABE: It would take two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): We have already taken a long time. Please speak, Mr. Schamnad.

SHRIMATI AMBIKA SONI: I would like to put on record that it is unfair.

DR. RAFIQ ZAKARIA: Why are we not allowed? Why are we not?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): I would like to tell the hon. Members that we have taken, I think, more than one-and-a-half hours. It is not the rule to allow more persons. Sometimes we allow. So, I request the Members not to insist.

SHRI S. W. DHABE: Why should you not allow us? This is a very strange way of doing things. I would request the Vice-Chairman not to be rigid.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Not rigid. You appreciate and sit down. Let us proceed.

SHRI S. W. DHABE: Why should you proceed?

DR. RAFIQ ZAKARIA: You have allowed two Members from there. You must allow two Members from here also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): That is not the rule.

Usually we allow one Member. Sometimes we allow more Members.

His name was there and he was insisting. So he was allowed.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH (Bihar): The Minister is prepared.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): The Minister is prepared and you are prepared, but time is not there. (*Interruptions*) Mrs. Ambika Soni, next time, some time later on, you can put it.

SHRI S. W. DHABE: One minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): No, please.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Only one clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): No, please; next time. (Interruptions) Every question has been asked . . .

SHRIMATI AMBIKA SONI: No, Sir. . . (Interruptions).

SHRI BIPINPAL DAS (Assam): Sir, all the Members are requesting. The Minister is ready. One minute you cannot allow:

DR. RAFIQ ZAKARIA: We will not allow you to proceed.

(Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): You cannot hold out a threat to the Chair. It is not fair. I cannot allow you under threat.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala): The Chairman has given his ruling.

(Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Please take your seats. (Interruptions). Mr. Dhabe, hear me. (Interruptions). I cannot allow.

DR. RAFIQ ZAKARIA: You have allowed two Members from there. You should allow two Members from here. (Interruptions).

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य (आन्ध्र प्रदेश) :
माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अगर एक क्षण
आप माननीय सदस्य को दे दें तो काफी समय
सदन का बच जायगा। मैं आपसे करबद्ध
प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक क्षण का समय आप
उनको दे दें। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा
हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) :
मेरे लिये सभी सदस्य समान हैं।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: If you had allowed her, it would have been over by now.

SHRI S. W. DHABE: Ten minutes you have taken. If you had allowed her, it would have been over by now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Well, let me hear her question.

SHRIMATI AMBIKA SONI: My question is, the hon. Minister in his reply said that there is no actual scarcity of kerosene or anything like that; it is just a psychological atmosphere; which has been created because a few hoarders, who are known to have been blackmailing the society in the past, have again hoarded some kerosene oil and that is why the poorer sections of the society cannot get it. Then this really underlines the importance of the public distribution system. Has the Central Ministry of Petroleum and Chemicals given any instructions to the State Governments, in regard to the kerosene that is allotted to each State, as to what should be the ratio of distribution between the rural and urban segments of the population?

SHRI H. N. BAHUGUNA: This is for the State Governments to decide. We do not give them such directions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Shri Schamnad.

REFERENCE TO THE GOVERNMENT'S ORDER PROHIBITING INDIANS FROM TAKING UP JOBS AS COOKS, OFFICE BOYS, ETC. ABROAD

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala): Sir, I would like to draw the attention of this House and also of the Minister of External Affairs to a very important matter, that is, the matter of great hardships, miseries and